

घटना घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatiगतana.com अम्बिकापुर, तृष 22, अंक - 148- मंगलवार 31- मार्च 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHN/2004/15050, डाक पंजीकरण क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सक्षिप्त समाचार

लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन दिल्ली में अरेस्ट



नई दिल्ली, 30 मार्च 2026। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक, शब्बीर दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं को भर्ती करने की तैयारी में था। यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था। साल 2007 में भी दिल्ली पुलिस ने आतंकीवाद के आरोपों में लोन को गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था। काठंडर इटैलिजेंस कश्मीर ने 26 मार्च को शब्बीर के आतंकी मोड्यूल की जांच के लिए कश्मीर के तीन जिलों, गंदरबल, शोपियां और श्रीनगर के 10 ठिकानों पर रेड मारी थी। CIJ के मुताबिक, इस मामले के तार एक टॉपिकेशनल नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं, जिसमें मोड्यूल को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स से निर्देश मिल रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां 2 महीनों से शब्बीर की गतिविधियों पर नजर रखे थीं।

आंध्र प्रदेश : नेवी कर्मचारी ने प्रेमिका के तीन टुकड़े किए थाने पहुंचकर अपराध कबूला



विशाखापत्तनम, 30 मार्च 2026। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक शादीशुदा नेवी कर्मचारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने शव के 3 टुकड़े किए। एक हिस्सा फ्रिज में छिपा दिया, दूसरा बोरे में भरकर बेड के नीचे रख दिया और तीसरा यानी सिर को सुनसान इलाके में ले जाकर जला दिया। वारदात के समय पत्नी मायके गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी चिंतादा रविंद्र (35) नेवी कर्मचारी हैं। वह आईएनएस डेगा में तैनात है। रविंद्र ने रविवार दोपहर अपनी 29 साल की प्रेमिका मोनिका को घर बुलाया था। शाम के समय दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर अपराध कबूल कर लिया। पुलिस के जांच में सामने आया कि रविंद्र ने मोनिका की चाकू से हत्या की। रविंद्र और मोनिका की मुलाकात 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी।

न्यू मैंगलोर पोर्ट के बर्थ-9 के पुनर्विकास को मंजूरी



नई दिल्ली, 30 मार्च 2026। केंद्र सरकार ने न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के बर्थ-9 के पुनर्विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत तरल बल्क कार्गो की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने और समुद्री दक्षता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत डीबीओएफओटी आधार पर लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत पुराने ढांचे को हटाकर बर्थ संख्या-9 का आधुनिक तरीके से पुनर्विकास किया जाएगा, जहां कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और एलपीजी जैसे तरल कार्गो की हैंडलिंग की जाएगी। परियोजना के तहत बर्थ की गहराई वर्तमान 10.5 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर की जाएगी, जिसे भविष्य में 19.8 मीटर तक बढ़ाने की व्यवस्था भी होगी। इससे 2 लाख डीडब्ल्यूटी तक के बड़े जहाजों, जिनमें बीएलजीसी भी शामिल हैं, को संभालना संभव होगा। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लोकसभा से दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पारित बस्तर से लाल आतंक खत्म, हथियार उठाने वालों को बरखेंगे नहीं : शाह

नई दिल्ली, 30 मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 'नक्सल मुक्त भारत' मुद्दे पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सालों से भोले-भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। शाह ने कहा... मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि आजादी के बाद 75 साल में 60 साल तो आपने राज किया। फिर आदिवासी विकास से क्यों बच गए। आपने 60 साल के दौरान आदिवासियों तक घर, स्कूल, मोबाइल टॉवर नहीं पहुंचने दिया और अब हिसाब मांग रहे हो। अपने गिरबान में झांकर देखिए। शाह ने कहा- 1970 से 2026 तक चले नक्सलवाद के घटनाक्रम की आज संसद में चर्चा हो रही है। जो लोग नक्सलवाद की वकालत करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ ये सब 1970 से अब तक क्यों नहीं हुआ था। संसद में आज नक्सलवाद पर चर्चा सरकार की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले हो रही है। शाह कई बार 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं।

शाह ने कहा... आदिवासियों के जरिए सत्ता खसित करना नक्सल विचारधारा का मकसद

शाह ने कहा... ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है उसका श्रेय सीपीएम के खासकर कोबरा, सीआरपीएफ के जवान और छातीसगढ़ पुलिस और वहां के स्थानीय आदिवासी बाशिंदों को जाता है। यहां पर वामपंथी उपादक समाप्त होने जा रहा है। इसमें वहां की जनता का भी



शाह बोले... नक्सलवाद का मूल कारण विकास नहीं, एक विचारधारा है...

शाह ने कहा... सरकार ने डेर सारी योजनाएं बनाई लेकिन आपने (कांग्रेस) उन्हें इमप्लीमेंट नहीं करने दिया। 12 राज्यों में रेड कॉरिडोर था। वहां कानून का शासन नहीं था। 12 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मौत हुई। एक NGO के मुताबिक, 20 हजार युवा मारे गए। लोग दिव्यांग हो गए। उन तक विकास नहीं पहुंचा। शाह ने कहा... इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं, एक विचारधारा है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया कि वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकारा था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी समस्या माओवादी है।

बहुत बड़ा हाथ है। जो हजारों युवा मारे गए, जो जवान शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। गृह मंत्री ने कहा... नक्सलियों की विचारधारा का विकास से कोई लेना-देना नहीं है। जब हम आजाद हुए हमने कहा 'सत्यमेव जयते'। सत्य

लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल पास

लोकसभा ने सोमवार को ध्वनि मत से हितधारकों के बीच व्याख्या संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए लाया गया दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पारित कर दिया। यह विधेयक का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 में और संशोधन करना है। लोकसभा ने आज ध्वनि मत से 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक-2025' पारित कर दिया। यह विधेयक शुरू में एक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। इसे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में और संशोधन करने के लिए पेश किया गया है, ताकि कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियागत देरी और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पर हुई विस्तृत चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता का उद्देश्य कभी भी केवल ऋण वसूली के तंत्र के रूप में काम करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य व्यवहार्य व्यवसायों को बचाने, वित्तीय संकट को हल करने और उद्यम के मूल्य को बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना था। सीतारामण ने चर्चा के दौरान कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) संशोधन विधेयक में कुल 12 संशोधन हैं, जिनमें से 11 चयन समिति के सुझाए गए हैं और एक सरकार ने पेश किया है।

महुआ बोर्ली- हमने वेलफेयर पर ओर देकर पश्चिम बंगाल को नक्सल मुक्त बनाया

महुआ मोड्डा ने नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान कहा कि आज देश राइटिंग आतंकवाद से त्रस्त है। एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए किसी रोडमैप की कोई बात नहीं हो रही है। आज आपने अचानक नक्सलवाद पर चर्चा शुरू करा दी। कितने महान हैं अमित शाह जी, सबको ठेक कर ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद 1969 में सिलीगुड़ी के पास नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ और बाकी जगह फैला। लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म कानून-व्यवस्था की परेशानी नहीं थी। आज बीजेपी दावा कर रही है कि हमने इस समस्या का समाधान कर दिया। मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे कदमों का इसमें बड़ा योगदान रहा। 2019 से 2025 के बीच किरिंग बड़ी, गिरफ्तारियां कम हुईं। सिक्किम रिप्लेटेड फंड्स 44 परसेंट खर्च नहीं हुए इस वित्तीय वर्ष में। महुआ मोड्डा ने 2011 से 2017 के बीच नक्सलियों के संरंद्ध के आंकड़े बताए और कहा कि हमने मिलिट्री पावर यूज नहीं की। हमने वेलफेयर पर जोर देकर पश्चिम बंगाल को नक्सल मुक्त बनाया।

नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद से तो नितिन नवीन का विधानसभा से इस्तीफा राज्यसभा में करेंगे नई पारी की शुरुआत

पटना, 30 मार्च 2026। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया? नीतीश के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब दोनों नेता राज्यसभा में अपनी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए थे, इसलिए 30 मार्च यानी आज उन्हें एक सदन से इस्तीफा देना था। राज्यसभा में जाने के बाद नीतीश कुमार उन गिने-चुने नेताओं की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया है। नीतीश कुमार ने 1985 में हरनौत (नालंदा) से पहली बार विधायक बनकर करियर की शुरुआत की। 1989 में बाढ़ (पटना) से पहली बार लोकसभा पहुंचे। नीतीश कुमार ने केंद्र में रेल मंत्री, कृषि



मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे में व्यापक सुधार लागू किए। नीतीश कुमार साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल रहे हैं और 'सुशासन बाबू' के रूप में अपनी पहचान बनाई। बिहार में शराबबंदी, साइकिल योजना और पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण जैसे क्रांतिकारी फैसलों का श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

कोलकाता, 30 मार्च 2026। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी, जिसके साथ ही राज्य में चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना दो अप्रैल को जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अप्रैल तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच सात अप्रैल को होगी। उम्मीदवार नौ अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल, जांच 10 अप्रैल और नाम वापसी की अंतिम तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की गई है।

सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित जालसाजी का आरोप, सुनवाई 18 अप्रैल को...

नई दिल्ली, 30 मार्च 2026। राजज एवैन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। सोनिया गांधी के खिलाफ बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त किए वोट लिस्ट में नाम जोड़ने की कथित जालसाजी की शिकायत की गई है। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच कराने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वकील विकास विपाठी की ओर से दाखिल रिवाज फिटिशन



पर अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी बहस पूरी कर दी, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान राजज एवैन्यू कोर्ट ने याचिकाकर्ता के

राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला... ईरान-रूस से तेल खरीदने के लिए ट्रंप से लेनी पड़ रही इजाजत



कोड्रायम, 30 मार्च 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोड्रायम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का वजह से भारत की अपनी मर्जी से तेल खरीदने की ताकत खत्म हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को ईरान या रूस जैसे देशों से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा और रबर किसानों के लिए बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ समझौता करके हमारे किसानों के अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। राहुल ने कहा कि आज भारत अपनी मर्जी से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य पूर्व के हालातों की वजह से आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन

मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, 'केरल के मुख्यमंत्री से कितने घंटे पूछताछ हुई? क्या वह जमानत पर बाहर हैं? क्या उनके बच्चों और उनके परिवार से पूछताछ की गई है? जब एलडीएफ नेतृत्व ने सबरीमाला मंदिर से सोना चुराकर उसकी जगह पीतल लगा दिया, तो प्रधानमंत्री इस पर कुछ क्यों नहीं कहते?' उन्होंने कहा कि पीएम खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताते हैं, लेकिन इस चोरी पर कुछ नहीं बोलते। हालांकि, राहुल गांधी के इन दावों पर पलटवार भी हो रहा है। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले भाषणों में सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। पीएम मोदी ने इसी साल जनवरी में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सबरीमाला का संप्रदायों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। पीएम ने वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है, तो सोने की चोरी की जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

असम में 10 साल में बीजेपी की विकास यात्रा नितिन बोले... कांग्रेस ने घुसपैठियों को अनुमति दी

गुवाहाटी, 30 मार्च 2026। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उसने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में प्रवेश करने की अनुमति दी। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद इनकी एंटी को रोकना और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया गया। एक चुनावी रैली में नवीन ने कांग्रेस

नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जब पारंपरिक असमिया 'गमोचा' पहनने का प्रस्ताव रखा गया, तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, जिससे असमवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची। वहीं, मस्तिष्क में जाते समय वह आराम से सिर पर टोपी पहनते हैं। नवीन ने कहा कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों का समर्थन किया।

जनगणना 2026 : पहले चरण के लिए 33 सवाल तय ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे, लिव-इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा

नई दिल्ली, 30 मार्च 2026। जनगणना-2026 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 33 सवाल जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव-इन कपल को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब ही होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। पहले चरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। उनकी मदद के लिए इस पोर्टल पर सख्त (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) संदर्भ तिथि (रेफरेंस डेट) बहुत महत्वपूर्ण है। यह चरण 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है, ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके। दूसरे चरण में भी जानकारी दे सकेंगे, लिव-इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा



जुड़ी डिटेल्स जानकारी ली जाएगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण कहते हैं, 'जनगणना की संदर्भ तिथि (रेफरेंस डेट) बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ समय 1 मार्च की आधी रात है, जो 28 फरवरी 2027 और 1 मार्च 2027 के बीच पड़ती है। इस संदर्भ तिथि का उल्लेख 16 जून 2025 को जारी पहली अधिसूचना में किया

गया था, जिसमें जनगणना कराने के इरादे की घोषणा की गई थी। इसी संदर्भ तिथि के कारण इसे जनगणना 2027 कहा जाता है। 16 जून, 2025 को अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 ही बनी हुई है। जनगणना के परिणामों से प्रत्येक प्रशासनिक इकाई, राज्य, जिले, गांव और वार्ड की जनसंख्या और विभिन्न आंकड़ों की एक झलक मिलेगी, जैसा कि वे 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे की स्थिति में होंगे। इसलिए यह संदर्भ तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जनगणना दो चरणों में की जाती है। पहला चरण 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' है, जिसमें घरों की सूची बनाना और उनकी गिनती करना शामिल है।

पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से...

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को बताया था कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने (सेल्फ एन्यूमेरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल, जनगणना 2021 में इसी ही, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से डोने टाल दिया गया था। यह अब 2027 में पूरी होगी।

इन 33 सवालों के जवाब देने होंगे...	
1. क्या आप पुरुष हैं?	16. क्या आप शादीशुदा हैं?
2. क्या आप महिला हैं?	17. क्या आप शादीशुदा हैं?
3. क्या आप शादीशुदा हैं?	18. क्या आप शादीशुदा हैं?
4. क्या आप शादीशुदा हैं?	19. क्या आप शादीशुदा हैं?
5. क्या आप शादीशुदा हैं?	20. क्या आप शादीशुदा हैं?
6. क्या आप शादीशुदा हैं?	21. क्या आप शादीशुदा हैं?
7. क्या आप शादीशुदा हैं?	22. क्या आप शादीशुदा हैं?
8. क्या आप शादीशुदा हैं?	23. क्या आप शादीशुदा हैं?
9. क्या आप शादीशुदा हैं?	24. क्या आप शादीशुदा हैं?
10. क्या आप शादीशुदा हैं?	25. क्या आप शादीशुदा हैं?
11. क्या आप शादीशुदा हैं?	26. क्या आप शादीशुदा हैं?
12. क्या आप शादीशुदा हैं?	27. क्या आप शादीशुदा हैं?
13. क्या आप शादीशुदा हैं?	28. क्या आप शादीशुदा हैं?
14. क्या आप शादीशुदा हैं?	29. क्या आप शादीशुदा हैं?
15. क्या आप शादीशुदा हैं?	30. क्या आप शादीशुदा हैं?
31. क्या आप शादीशुदा हैं?	32. क्या आप शादीशुदा हैं?
32. क्या आप शादीशुदा हैं?	33. क्या आप शादीशुदा हैं?

छत्तीसगढ़ के विमानन क्षेत्र में नया अध्याय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अम्बिकापुर-दिल्ली-कोलकाता हवाई सेवा का किया वर्चुअल शुभारंभ

उत्तर छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान व्यापार, पर्यटन और निवेश के खुलेंगे द्वार : मुख्यमंत्री साय

अम्बिकापुर (दरिमा) से दिल्ली और कोलकाता के लिए सप्ताह में दो-दो दिन संचालित होंगी उड़ानें



सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली हवाई सेवा के बने पहले यात्री

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ के विमानन मंत्रालय पर एक नया गौरवशाली अध्याय जोड़ते हुए अम्बिकापुर (दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट) से दिल्ली और कोलकाता के लिए नियमित हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। वहीं अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक साक्षी बने।

ऐतिहासिक उपलब्धि और सुगम आवागमन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में इस दिन को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। दरिमा एयरपोर्ट से महानगरों के लिए विमान सेवा की लंबे समय से की जा रही मांग आज पूरी हुई है। इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजंपु राममोहन नायडू का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा के प्रारंभ होने से अम्बिकापुर, बिलासपुर, दिल्ली और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आवागमन सुगम बनेगा। अम्बिकापुर से दिल्ली तथा कोलकाता के लिए सप्ताह में दो-दो दिन उड़ान संचालित होगी, जिससे सरगुजा एवं



बिलासपुर क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन उड़ानों के शुरू होने से अम्बिकापुर, बिलासपुर, दिल्ली और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी। सप्ताह में दो-दो दिन इन सेवाओं के संचालन से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के नागरिकों को अब सीधे देश की राजधानी और पूर्वी भारत के प्रमुख महानगर कोलकाता तक पहुंचने में आसानी होगी।

आर्थिक और औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार 'विकसित छत्तीसगढ़' के लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जो विकसित भारत के अनुरूप है। हवाई सेवाओं का विस्तार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश को लगातार लाभ मिल रहा है। हाल ही में रायपुर से रीवा के लिए भी विमान सेवा शुरू की गई है। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रकाश डालते हुए



उन्होंने बताया कि पिछले बजट में रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 39.80 करोड़ रुपये तथा जगदलपुर एवं दरिमा एयरपोर्ट के विकास हेतु 7.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान बजट में 'सीजी वायु योजना' के तहत 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा मिली है और नाइट लैंडिंग और टेकऑफ की शुरुआत भी की गई है, जो राज्य के एविएशन सेक्टर की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एविएशन सेक्टर राज्य के आर्थिक विकास और निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न शहरों में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से निवेशकों में छत्तीसगढ़ के प्रति उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य अब कृषि और मैन्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ

हवाई कनेक्टिविटी से समय की बचत और विकास को मिलेगी रफ्तार

पर्यटन, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें हवाई सेवाओं का विस्तार नई गति प्रदान करेगा। अंत में उन्होंने अम्बिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए विमान सेवा प्रारंभ होने पर सरगुजा वासियों, प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि अब अम्बिकापुर से सीधे दिल्ली एवं कोलकाता पहुंचने में सुविधा प्राप्त होगी तथा हवाई कनेक्टिविटी से कम समय में हम आसानी से पहुंच जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड्डयन मंत्री एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह प्रतीक्षित हवाई सेवा दिल्ली एवं कोलकाता के लिए प्रारंभ हो गई है यह अम्बिकापुर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के

सहित संभाग के लोगों को दिल्ली एवं कोलकाता पहुंचने में सुविधा मिलेगी तथा पर्यटन, संस्कृति एवं व्यापार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, सरगुजा संभागयुक्त नरेंद्र दुर्गा, आईजी दीपक झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

एलायंस एयर का फ्लाइट शेड्यूल (सप्ताह में 4 दिन)

विमानन कंपनी एलायंस एयर द्वारा इन उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभ हो चुकी है।

दिल्ली रूट (सोमवार और बुधवार)

सोमवार (फ्लाइट नं. 91613) दिल्ली से बिलासपुर होते हुए सुबह 11:35 बजे अम्बिकापुर पहुंचेंगे। वापसी में दोपहर 12:00 बजे अम्बिकापुर से सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। बुधवार (फ्लाइट नं. 91614) दिल्ली से सुबह 10:25 बजे अम्बिकापुर आगमन और दोपहर 12:00 बजे बिलासपुर होते हुए दिल्ली प्रस्थान करेंगी।

कोलकाता रूट (गुरुवार और शनिवार)

शनिवार (फ्लाइट नं. 91763) कोलकाता से बिलासपुर होते हुए सुबह 10:00 बजे अम्बिकापुर आगमन और 10:25 बजे सीधे कोलकाता प्रस्थान करेंगी। गुरुवार (फ्लाइट नं. 91765) कोलकाता से सुबह 08:50 बजे अम्बिकापुर आगमन और 09:15 बजे बिलासपुर होते हुए कोलकाता प्रस्थान करेंगी।

हैडपंप को लेकर विवाद, युवक पर टांगी से हमला, इलाज के दौरान मौत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

लुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम पटोरा में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। हैडपंप चलाने की बात पर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने युवक पर टांगी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, ग्राम पटोरा जोबलापारा निवासी राकेश (20) पिता स्व. बनारसी 29 मार्च को अपने दोस्तों रामसाय और संजय के साथ बाइक से ग्राम करेसर गया था। अटल चौक के पास उसे गांव का ही लूर साय मिला, जो जंगल की खवाली करता है। राकेश ने पानी पीने के लिए लूर साय से हैडपंप चलाने को कहा। इस बात पर लूर साय नाचने लगे और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर लूर साय ने अपने पास रखी टांगी से राकेश के दाहिने पैर के घुटने के पास वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों और पुलिस ने घायल को धौपुर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, घुटने के पास नस कटने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी जान गई। लुण्डा थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि घटना मामूली विवाद में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन आरोपी फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए टीम लगाई गई है।



मन की बात' सुनकर उत्साहित हुए भाजपा कार्यकर्ता भगवानपुर वार्ड-1 में प्रदेश महामंत्री की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

शहर के वार्ड क्रमांक-1 भगवानपुर में रविवार को प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी एवं वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर की विशेष उपस्थिति रही, जहां समलाया मंडल के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम के उपरांत प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करते हुए सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि 'मन की बात' एक ऐसा मंच है, जो हर नागरिक को प्रेरित करता है और सामाजिक एकता तथा राष्ट्रहित के लिए कार्य करने की दिशा दिखाता है। समलाया मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं एवं आमजन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विचारों से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

आईजी दीपक झा का वार्षिक निरीक्षण, अनुशासन व पारदर्शिता पर दिया जोर...

परेड की सलामी ली, उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को किया पुरस्कृत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) दीपक कुमार झा ने सोमवार को सरगुजा जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रक्षित केंद्र अम्बिकापुर में परेड की सलामी ली और पुलिस बल के अनुशासन, वेश-भूषा व कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने रक्षित केंद्र में उपलब्ध शासकीय वाहनों की स्थिति देखा और उनके नियमित रख-रखाव के निर्देश दिए। साथ ही कैश शाखा, स्टोर शाखा और पुलिस कैटीन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश संबंधित



अधिकारियों को दिए। इसके बाद आयोजित पुलिस दरवार में आईजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

नशा व भ्रष्टाचार से दूर रहने की हिदायत

उन्होंने पुलिस बल को नशे और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण कार्यों का लोकार्पण

निरीक्षण के दौरान आईजी ने पीसीएंडआर मद से रक्षित केंद्र में कराए गए विभिन्न निर्माण व मरम्मत कार्यों जैसे बाउंड्री वॉल, मीटिंग हॉल, विशेष शाखा रिनोवेशन और परेड मंच का लोकार्पण भी किया। इससे पहले उन्होंने थाना गांधीनगर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा कार्यालयीन कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

पालन की सलाह दी। उन्होंने आधुनिक ज्ञान को आवश्यक बताते हुए सभी के पुलिसिंग के लिए कंप्यूटर और तकनीकी इस्तेमाल के निर्देश दिए।

जेलों में शुरू होगी वीडियो-ऑडियो कॉलिंग सुविधा, बंदी अब परिवार से कर सकेंगे सीधे बात

बीएसएनएल के साथ एमओयू, राज्य की 33 जेलों में लगेगा प्रिजन कॉलिंग सिस्टम

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की जेलों में बंदियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब बंदी अपने परिवारों और वकीलों से वीडियो कॉल के जरिए सीधे बातचीत कर सकेंगे। इसके लिए जेल मुख्यालय और बीएसएनएल के बीच सोमवार को एमओयू किया गया। जेल विभाग के अनुसार, इस समझौते के तहत राज्य की सभी 33 जेलों में बीएसएनएल द्वारा नि:शुल्क वीडियो और ऑडियो प्रिजन कॉलिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह पहल बंदियों के मानवीय अधिकारों और उनके सामाजिक पुनर्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण



कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय तक परिवार से दूरी के कारण बंदियों में तनाव और अवसाद बढ़ता है। ऐसे में यह सुविधा उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगी और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएगी। पहले चरण में इन जेलों में सुविधा : प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर को केंद्रीय जेलों सहित कई जिला जेलों में वीडियो और ऑडियो कॉलिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। अन्य जेलों में चरणबद्ध तरीके से सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

कम खर्च में मिलेगा लाभ

: इस व्यवस्था के तहत बंदियों को सप्ताह में एक बार 5 मिनट के लिए कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। ऑडियो कॉल के लिए 1 रुपए प्रति मिनट और वीडियो कॉल के लिए 5 रुपए प्रति मिनट शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे परिवारों को जेल आने-जाने में लगने वाला समय और खर्च भी बचेगा।

मुफ्त में उपलब्ध कराएगा बीएसएनएल सिस्टम

बीएसएनएल द्वारा सभी मशीन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। जेल विभाग का मानना है कि इस पहल से जेल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और बंदियों के पुनर्वास को नई दिशा मिलेगी।

साइबर टगी से अर्जित रकम की हेरफेर के मामले तीन आरोपी गिरफ्तार

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना पुलिस ने बैंक खाते किराए पर देकर साइबर टगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा लोगों को झूसे में लेकर उनके खातों का उपयोग ऑनलाइन टगी की रकम के लेन-देन में किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, गांधीनगर निवासी शौर्य प्रताप ने 29 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि परिचित ऋत्विक् सिंह ने दिसंबर 2024 में डेयरी व्यवसाय के नाम पर 48,500 रुपए अपने खाते से निकलवा लिए। इसके बाद उसका बैंक खाता ब्लॉक हो गया। जांच में पत चला कि खाते का उपयोग साइबर टगी की रकम के लेन-देन में हुआ है। जांच में सामने आया गिरोह : मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ऋत्विक् सिंह और उसके साथी अमन गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने कबूल किया कि वे अन्य साथियों के साथ मिलकर बैंक खाते की खरीद-फरोख्त करते थे और इन्हीं खातों के जरिए टगी की रकम ट्रांसफर करते थे। इसके अलावा आरोपी पिपूष तिवारी के खाते में भी कई सदिष्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पाए गए। पूछताछ में उसने भी अपराध में शामिल होना स्वीकार किया।

मोबाइल व डाटा जबर : पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, जिनमें खातों और लेन-देन से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा मिल है। मामले में साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

खड़गावां में सड़क नहीं, भ्रष्टाचार बिछा है, करोड़ों की सड़क 48 घंटे में खत्म PWD की पोल खुली: बनते ही उखड़ी सड़क, जिम्मेदार कौन?

करोड़ों डकार गए ठेकेदार... सड़क बनी और तुरंत बिखर गई...

- मिट्टी पर डामर चढ़ाकर खेल खत्म... खड़गावां में खुला भ्रष्टाचार...
- सरकारी पैसे की LIVE लूट, सड़क बनी और आंखों के सामने टूट गई

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गावां, 30 मार्च 2026 (घटती-घटना)। खड़गावां विकासखंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों ने विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन सड़कों को वर्षों तक टिकाऊ होना चाहिए था, वे निर्माण के महज कुछ ही दिनों-कहीं-कहीं घंटों-में ही उखड़ती नजर आ रही हैं, यह मामला न केवल निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि विभागीय निगरानी, तकनीकी मानकों और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर आरोप खड़े करता है।

निर्माण के तुरंत बाद उखड़ने लगी सड़कें-

खड़गावां मुख्यालय में कूड़ाकूड़ा से कवचा मार्ग तक बनाई गई सड़क, जिसका निर्माण आयुष फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंस्टीट्यूट द्वारा कराया गया, निर्माण के तुरंत बाद ही खराब होने लगी, हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय ग्रामीण अपने हाथों से डामर उखाड़ते नजर आए। वाहनों के सामान्य आवागमन से ही सड़क की परतें टूटकर बिखर रही हैं, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की सतह कमजोर है, डामर की परत निर्धारित मोटाई के अनुसार नहीं डाली गई, निर्माण में जल्दबाजी और लापरवाही साफ दिखती है।

तकनीकी मानकों की खुली अनदेखी

सड़क निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं जैसे डब्ल्यूबीएम (वाटर बाउंड मैकेडम) और डब्ल्यूएमएम का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, सामान्यतः इन सामग्रियों को प्लांट में मिक्स कर रोडर से दबाकर मजबूत बेस तैयार किया जाता है, लेकिन यहां यह प्रक्रिया या तो अधूरी रही या पूरी तरह नजरअंदाज की गई, इसके अलावा मिट्टी की सफाई किए बिना सीधे डामरीकरण कर दिया गया, रोडिंग और लेवलिंग का काम ठीक से नहीं हुआ, गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया संदिग्ध रही, इन सभी खामियों के कारण सड़क टिकाऊ नहीं बन पाई।

जनता के टैक्स की खुली बर्बादी

करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क का यह हाल दर्शाता है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है, गुणवत्ता नियंत्रण पूरी तरह विफल रहा है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई का अभाव है, ग्रामीणों का कहना है कि जिन सड़कों को वर्षों तक चलना चाहिए, वे एक दिन भी नहीं टिक पा रही।

'सेटिंग' का खेल : ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत?

जब ग्रामीणों ने घंटिया निर्माण का विरोध किया, तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने कथित रूप से कहा सारा काम सेटिंग से चल रहा है, जहां शिकायत करनी है कर लो, यह बयान इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है, इससे यह संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता नहीं है और ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के बीच साटगाट की संभावना है।

इंजीनियर की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

लोक निर्माण विभाग में पदस्थ इंजीनियर एस.के. लोध की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, ग्रामीणों के अनुसार वे निर्माण स्थल पर शायद ही कभी मौजूद रहते हैं, फोन कॉल का जवाब नहीं देते, निर्माण कार्य की निगरानी प्रभावी नहीं है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह केवल लापरवाही है या जानबूझकर की गई अनदेखी?

मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनदेखी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए थे कि निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए, दोषी अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जाएं, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसके बावजूद खड़गावां में इस प्रकार की लापरवाही सामने आना प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवाल खड़े करता है।

सूचना बोर्ड तक नहीं, पारदर्शिता गायब

निर्माण कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे परियोजना की लागत, ठेकेदार का नाम, निर्माण अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता से छिपी हुई हैं, यह पारदर्शिता के नियमों का सीधा उल्लंघन है।



ग्रामीणों में आक्रोश... जांच की मांग...

स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर भारी नाराजगी है, ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, भविष्य में गुणवत्ता से सम्झौता न किया जाए।

विकास या दिखावा?

खड़गावां की यह घटना केवल एक खराब गुणवत्ता का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम में व्याप्त खामियों और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है, जहां एक ओर सरकार 'मॉडल सड़क' और 'सुशासन' की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्य दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, अब देखा जाना चाहिए कि यह मामला कार्रवाई तक पहुंचता है या फिर अन्य मामलों की तरह फाटलों में दबकर रह जाता है।

संजय पार्क में हिरणों की मौत की जांच तेज, कांग्रेस जांच दल ने किया निरीक्षण डीएफओ से मुलाकात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व वीडियोग्राफी की मांग



-संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित 6 सदस्यीय जांच दल ने सोमवार को संजय पार्क का दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सरगुजा रेंज के डीएफओ से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर जानकारी ली। जांच दल का नेतृत्व पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कर रहे हैं। टीम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, पूर्व श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष शशी अहमद, प्रदेश

महामंत्री द्वितेंद्र मिश्र, जिला महामंत्री हेमंत तिवारी और अनुप मेहता शामिल हैं। दल ने हिरणों के बेहो, मृत वन्यजीवों को रखने के स्थान, पोस्टमार्टम स्थल और दाह संस्कार स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पार्क की देखरेख करने वाली समिति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। जांच दल ने डीएफओ से पार्क की देखरेख कर रही समिति की वैधानिकता और वन विभाग की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल किए। साथ ही मृत हिरणों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरी घटना की वीडियोग्राफी की मांग की गई।

कुत्तों के प्रवेश पर उठे सवाल : मीडिया से चर्चा में अमरजीत भगत ने कहा कि जिस स्थान से कुत्तों के बाड़े में घुसने की बात कही जा रही है, वह प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्क की देखरेख करने वाली समिति को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। जांच दल ने कहा कि रिपोर्ट जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और इसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

5 साल से बिना अनुमति चल रहा था संजय पार्क? हिरणों की मौत पर उठे तीखे सवाल 2023 में 50 हिरण गायब हुए, तब कोई क्यों नहीं बोला : सत्यम द्विवेदी

रात 3 बजे घटना सूचना 6:30 बजे... जिम्मेदार कौन?

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

संजय पार्क में हुई घटना को लेकर अब सवालों की बाखुर शुरू हो गई है। नैकमन सत्यम द्विवेदी ने पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि वर्षों की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्षों



से बिना Central Zoo Authority (CZA) की अनुमति के पार्क का

संचालन होता रहा, लेकिन आज तक किसी ने इस पर सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा। 'अगर नियमों का पालन होता, तो शायद आज यह स्थिति नहीं बनती,' उन्होंने कहा। द्विवेदी ने वर्ष 2023 में 50 से अधिक हिरणों के गायब होने के मामले को उठाते हुए कहा कि उस समय भी मामले को दबा दिया गया और किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वन्य प्राणियों का इलाज विशेषज्ञों के बजाय सामान्य पशु चिकित्सकों से कराया जाता रहा, जो गंभीर लापरवाही है।

सुरक्षा पर भी सवाल : उन्होंने पूछा कि आखिर पार्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? 'अगर समिति चौकीदारी कर रही थी तो वन विभाग क्या कर रहा था?' घटना के दिन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि रात 3 बजे कुत्तों द्वारा हिरणों पर हमला हुआ, लेकिन इसकी सूचना सुबह 6:30 बजे दी गई, जो सीधे तौर पर लापरवाही को दर्शाता है। अभद्रता और अंदरूनी विवाद भी सामने आए : द्विवेदी ने बताया कि सह प्रभारी ममता पोटे

के साथ समिति के उपाध्यक्ष के पति द्वारा सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज की गई, जिसकी शिकायत भी की गई है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की।

ऑडिट आदेश के बाद घटना पर उठे सवाल

उन्होंने यह भी कहा कि जब डीएफओ द्वारा समिति के अध्यक्ष का पुनः चुनाव और आय-व्यय के ऑडिट के निर्देश दिए गए, तो उसके अगले ही दिन ऐसी घटना होना कई संदेह पैदा करता है।

3 साल से अधूरी 'नल-जल योजना': सरगावां के सूखे नल, प्यासे ग्रामीण

-सुदामा राजवाड़े- बलरामपुर, 30 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना का जमीनी सच बलरामपुर जनपद के ग्राम पंचायत सरगावां में बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहा है। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का वादा यहां पिछले तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है और योजना पूरी तरह ठप हो चुकी है। गांव में न तो पाइपलाइन का अधूरा कार्य पूरा किया जा रहा है और न ही पानी टंकी का निर्माण आगे बढ़ाया गया है। हालात यह हैं कि घर-घर लगाए गए नल अब शीपीस बनकर रह गए हैं-सूखे, बंकर और ग्रामीणों की मजबूरी का प्रतीक। ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 2023 में बड़े उसाह के साथ योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद काम रुक



गया। कई घरों में पाइपलाइन आधी-अधूरी बिछाई गई, जबकि बड़ी संख्या में परिवार आज भी इस सुविधा से पूरी तरह वंचित हैं।



पानी के लिए लोगों को दूर-दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़

रहा है, जिन्हें योजना पानी लेने की मशक्कत करनी पड़ती है। दो साल से काम बंद होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की निष्क्रियता ने ग्रामीणों के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। लोगों का कहना है कि जब योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। इस मामले में पीएचडी विभाग की सहायक अभियंता सुनील उरांव ने बताया कि पूर्व ठेकेदार द्वारा काम अधूरा छोड़ दिया गया था। अब नए ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर उसे पूरा किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या 'हर घर नल जल' योजना सरगावां में सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगी, या फिर प्रशासन समय रहते जागृता और प्यासे ग्रामीणों को राहत मिलेगी?

मवेशी तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार दो पिकअप व एक कार जब्त, 14 मैस बरामद



-संवाददाता- बलरामपुर, 30 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलंगी चौकी इलाके में पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो पिकअप वाहन, एक ग्रैंड विटारा कार तथा 14 नग भैंस/भैंसी बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि बलंगी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध मवेशी तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर एसडीओपी वाइफनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 28-29 मार्च की मध्यराति चौकी बलंगी में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस

दौरान तेज गति से आ रहे संदिग्ध वाहनों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरियर लगाकर घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान दो पिकअप वाहनों को पकड़ लिया गया, जबकि उनके चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों में 7-7 नग भैंस लदी मिली। इसी दौरान एक संदिग्ध ग्रैंड विटारा कार (सीजी 30 जी-5161) को भी मौके से जब्त कर उसके चालक जितेंद्र कुमार जायसवाल निवासी केसारी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने मानिकचंद सोनवानी, दीपक सोनवानी एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर मवेशी तस्करी करने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी सामने आया कि तस्करी से प्राप्त राशि आरोपी मानिकचंद सोनवानी की पत्नी देवमती सोनवानी के बैंक खाते में जमा की जाती थी।

लुण्ड्रा में विकास को नई गति : विधायक प्रबोध मिंज ने 2.84 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया भूमि पूजन

-संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्रीय विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने ग्राम पंचायत चट्टीरमा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया, इस अवसर पर कुल 2 करोड़ 84 लाख 72 हजार रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों की शुरुआत की गई, जिससे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। खेल मैदान में मंच एवं शोड निर्माण से बढ़ेगी सामाजिक गतिविधियां-कार्यक्रम का आयोजन ग्राम बहूनी झरिया स्थित खेल मैदान में किया गया, जहां 2 लाख रुपये की लागत से मंच एवं शोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, इस निर्माण से गांव में आयोजित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रमों को बेहतर मंच मिलेगा, साथ ही युवाओं और ग्रामीणों को एक स्थायी स्थान उपलब्ध होगा। 2.84 करोड़ की सड़क परियोजना: गांव से शहर तक मजबूत कनेक्टिविटी-कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री अग्रसेन गौशाला रोड चट्टीरमा से मेंडराखुर्द तक सड़क निर्माण का भूमि पूजन रहा, जिसकी लागत 284.72 लाख रुपये है, यह सड़क गांव को मुख्य मार्गों और शहर से



जोड़ेगी, आवागमन को सुगम बनाएगी, बरसात के समय होने वाली समस्याओं को कम करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को गति देगी स्थानीय लोगों के अनुसार, यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांगों में शामिल थी। विधायक का संदेश : सड़क विकास की रीढ़ - विधायक प्रबोध मिंज ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास की रीढ़ होती है, उन्होंने कहा बेहतर सड़क से मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, छात्रों को स्कूल और कॉलेज तक पहुंचने में सुविधा होगी, किसानों और व्यापारियों को बाजार



तक पहुंच आसान होगी, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा होंगे, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

जनसंवाद और त्वरित समाधान की पहल- भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद विधायक ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया, उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, इस पहल से ग्रामीणों में भरोसा और संतोष का माहौल देखने को मिला। भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद-कार्यक्रम में विधायक का लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ से भव्य स्वागत किया गया, इस अवसर पर प्रमुख रूप से भरत सिंह सिंसोदिया (भाजपा जिला अध्यक्ष), दिव्या सिंह सिंसोदिया (जिला पंचायत सदस्य), विनोद हर्ष, अरुणा सिंह (जिला महामंत्री), विजय व्यापारी (जनपद सभापति), संतोष जायसवाल (मंडल अध्यक्ष), रवि उरांव (पार्षद), अमृत लाल यादव (युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष), सरिता मिश्रा (महिला मोर्चा महामंत्री), सोनिया पंडो (सरपंच, चट्टीरमा), हीरामणि सोनपाकार (सरपंच, मेंडराखुर्द) प्रीति सिंह (सरपंच, डिंगमा) सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे।

'सहयोग' या 'वसूली'?

कर्मा जयंती में नया विवाद...

वायरल चैट, बड़ा सवाल



-रवि सिंह-
कोरिया, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।
सूरजपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति जहां एक ओर सामाजिक एकता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी गई, वहीं

सूरजपुर में आयोजन, कोरिया में सवाल: आखिर पैसा किस बात का ?

दूसरी ओर कोरिया जिले में उसी कार्यक्रम को लेकर आर्थिक वसूली के आरोपों ने विवाद को समाज के भीतर खुली बहस और असंतोष का कारण बन गया है।

- सूरजपुर का कार्यक्रम, कोरिया में बवाल: 'सहयोग राशि' पर समाज में संग्राम
- सरकारी मंच, समाज का फंड! कर्मा जयंती में 'सहयोग' या 'वसूली'?
- जयकारों के बीच जमा होती रही राशि? कर्मा जयंती पर उठे सवाल
- भक्ति के साथ बिल भी? कार्यक्रम के बाद 'सहयोग राशि' पर घमासान
- सरकारी प्रोटोकॉल में आयोजन, फिर भी वसूली? कोरिया में उठा विवाद
- कार्यक्रम बना सियासत का मुद्दा, कोरिया में समाज के भीतर टकराव

आस्था के मंच पर विवाद की परछाई
सूरजपुर का यह आयोजन जहां सामाजिक आस्था, एकता और राजनीतिक उपस्थिति का बड़ा मंच बना, वहीं कोरिया में उठे वसूली के आरोपों ने इसकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं, यदि समय रहते स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तो यह विवाद समाज के भीतर गहरी दरार का कारण बन सकता है।

डिस्क्लेमर
यह समाचार विभिन्न स्थानीय स्रोतों, सामाजिक चर्चाओं एवं वायरल व्हाट्सएप चैट में सामने आए दावों के आधार पर तैयार किया गया है, प्रस्तुत जानकारी में लगाए गए वसूली संबंधी आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, समाचार का उद्देश्य केवल तथ्यों एवं उठ रहे सवालों को प्रस्तुत करना है, संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समाचार को अद्यतन किया जाएगा।

व्हाट्सएप चैट वायरल, आरोपों को मिला आधार
विवाद तब और गहरा गया जब कोरिया जिले के सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप का कथित चैट वायरल हो गया, इस चैट में कार्यक्रम के नाम पर राशि एकत्र करने की चर्चा सामने आई, जिसके बाद समाज के भीतर ही विरोध के स्वर तेज हो गए, सूत्रों के अनुसार, कोरिया जिले से करीब 2 लाख रुपये से अधिक राशि जुटाए जाने की बात चर्चा में है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

समाज के भीतर पहले से मौजूद असंतोष
यह विवाद अचानक नहीं उभरा, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, कोरिया जिले में समाज के अध्यक्ष चुनाव को लेकर पहले ही मतभेद और विरोध की स्थिति बनी हुई है, नव-निर्वाचित अध्यक्ष को लेकर आपत्तियां, समाज के भीतर गुटबाजी, ऐसे में सूरजपुर कार्यक्रम से जुड़ा वसूली का मुद्दा इस असंतोष को और उभारने का कारण बन गया है।

प्रशासन और आयोजकों की चुप्पी
अब तक इस मामले में न तो प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आई है और न ही समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट की है, इस चुप्पी ने विवाद को और हवा देने का काम किया है।

बता दे सूरजपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी ने आयोजन को भव्य बना दिया, लेकिन कार्यक्रम के बाद कोरिया जिले में उठे 'सहयोग राशि' (वसूली) के आरोपों ने पूरे आयोजन को बहस के कटघरे में ला खड़ा किया है, आस्था के मंच पर जहां जयकारे गूँजे, वहीं पीछे से 'राशि जमा कर दीजिए' की आवाजें भी चर्चा में आ गईं।

मत्व आयोजन, मजबूत सरकार की उपस्थिति
सूरजपुर जिला मुख्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम समाज विशेष के आराध्य से जुड़ा धार्मिक आयोजन था, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए, पूरे आयोजन में प्रशासनिक तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से शासकीय स्तर के अनुरूप नजर आए, संभाग के विभिन्न जिलों से समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे आयोजन का व्यापक स्वरूप सामने आया।

आरोपों की शुरुआत: जब सरकार आयोजन, तो फिर वसूली क्यों?
कार्यक्रम के बाद कोरिया जिले में समाज के कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाए गए कि जब कार्यक्रम शासकीय प्रोटोकॉल के तहत आयोजित था मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी थी तो समाज के लोगों से आर्थिक सहयोग (राशि) क्यों मांगी गई? यही सवाल अब विवाद का मुख्य केंद्र बन गया है।
वायरल चैट: श्रद्धा का स्क्रिनशॉट या वसूली का सबूत?
कोरिया जिले के एक सामाजिक व्हाट्सएप समूह का कथित चैट सामने आने के बाद विवाद ने रफतार पकड़ ली, चैट में साफ तौर पर लिखा गया— जो सहयोग राशि इकट्ठा किए हैं, आज ही जमा करें... अब यह लाइन ही पूरे विवाद की आत्मा बन गई है, क्योंकि सवाल सीधा है— सहयोग था या निर्देश? सूत्र बताते हैं कि करीब 2 लाख रुपये से अधिक राशि कोरिया जिले से एकत्र होने की चर्चा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा इतनी है कि अब यह मुद्दा चाय की टपरी से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस तक पहुंच चुका है।

सूरजपुर में दो बड़े खुलासे: पत्नी की हत्या कर खुद रिपोर्ट लिखाने वाला पति गिरफ्तार, नकली सोना ठगी गैंग भी पकड़ा



**-संवाददाता-
सूरजपुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।**
जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ओर पत्नी की हत्या कर खुद को बचाने की कोशिश करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर नकली सोना देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच ने सच्चाई सामने ला दी। सूरजपुर में सामने आए ये दोनों मामले यह दर्शाते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी चालाकी से योजना बनाए, पुलिस की सघन जांच से बच पाना मुश्किल है। एक ओर धोखे विवाद ने हत्या का रूप लिया, तो दूसरी ओर लालच का फायदा उठाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया— लेकिन दोनों ही मामलों में कानून ने तेजी से शिकंजा कस दिया।



पत्नी की हत्या कर खुद पहुंचा पुलिस चौकी, जांच में खुला राज
चौकी सलका-उमेशपुर क्षेत्र के ग्राम तारकेशपुर निवासी अलमा प्रजापति ने 4 मार्च 2026 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी लीलावती की मौत अज्ञात कारणों से हो गई है, उसने बताया था कि वह 3 मार्च को बाहर गया हुआ था और लौटने पर पत्नी को जमीन पर पड़ा पाया, शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध मौत का लगा, लेकिन मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला हत्या का निकला। जांच में सामने आया कि आरोपी अलमा प्रजापति का अन्य महिलाओं से बातचीत को लेकर पत्नी से अक्सर विवाद होता था, जिसके चलते वह मारपीट भी करता था, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि घटना की रात पत्नी द्वारा चरित्र पर संदेह जताने पर उसने गुरसे में आकर हाथ-पैर, प्लास्टिक पाइप और चाकू से हमला कर हत्या कर दी, बाद में खुद को बचाने के लिए उसने मगदंत कहानी बनाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और पाइप बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी क्षेत्र का पुराना गुंडा बदमाश भी बताया जा रहा है।
नकली सोना दिखाकर 4.40 लाख की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार
दूसरे मामले में थाना चांदनी पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम दरौपारा निवासी बालरूप गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने पहले असली सोने का सैंपल दिखाकर भरसा जीता और बाद में पीतल को सोने जैसा बनाकर उसे बेच दिया, घटना के अनुसार, आरोपियों ने 11 मार्च 2026 को रेडीपहरी चौक टाडपाथर में नकली सोना देकर प्रार्थी से कुल 4 लाख 40 हजार रुपये ठग लिए, पुलिस ने मामले की जांच कर अर्जुन देवांगन, मोहन उर्फ सोनू, राजेन्द्र यादव और किशोरी लाल यादव को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 1 लाख 24 हजार रुपये नगद भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सभी ने अपराध स्वीकार कर लिया है।
पुलिस की सख्ती से उजागर हुए दोनों मामले-
दोनों ही मामलों में डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मार्गदर्शन में स्थानीय पुलिस टीमों ने सटीक जांच और तकनीकी आधार पर अपराधों का खुलासा किया।



नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

**-संवाददाता-
कोरिया/पटना, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।**
थाना पटना क्षेत्रांतर्गत नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है, आरोपी द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विद्यालय में नौकरी लगाने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपये चेंटे गए।
आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनाने के नाम पर ठगी
प्रार्थिया आरती पटेल, निवासी ग्राम तेंदुआ, थाना पटना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि टेंगनी निवासी आरोपी संदीप सिंह सारथी ने दिसंबर 2024 में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया, आरोपी ने उससे अलग-अलग किश्तों में लगभग 2,40,000/- के साथ 44,000/- एवं 24,750/- की अतिरिक्त राशि ली, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई और रकम हड़प ली।

भ्रामक खबरों पर सख्ती: बलरामपुर में मीडिया मॉनिटरिंग दल का गठन

**-संवाददाता-
बलरामपुर, 30 मार्च 2026
(घटती-घटना)।**
पश्चिम एशिया में उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के बीच आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर फेल रही अफवाहों और भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर जिले में मीडिया मॉनिटरिंग दल का गठन किया गया है। यह दल फ्रिट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों की लगातार निगरानी करेगा। विशेष रूप से एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, उर्वरक और अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखते हुए आम नागरिकों तक सही और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाई जाएगी। मॉनिटरिंग दल के नोडल अधिकारियों के रूप में अफ कलेक्टर चेतन बोरघरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जिला जनसंपर्क अधिकारी देविका मरावी को भी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या अप्रुष्ट जानकारी सामने आने पर तत्काल उसकी तथ्य जांच कर सही जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अफवाहों पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण किया जा सके और जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी



शिक्षक भर्ती के नाम पर दो और पीड़ित

जांच में सामने आया कि आरोपी ने स्तुति पटेल और प्रियंका कुजूर को आत्मानंद विद्यालय में शिक्षक पद पर नौकरी दिलाने का लालच देकर दोनों से 1,80,000/-, 1,80,000/- की ठगी की। आरोपी ने किसी भी पीड़ित को नौकरी नहीं दिलाई।
अपराध दर्ज, विवेचना में हुआ खुलासा
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 89/2026, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, जांच के दौरान आरोपी द्वारा ठगी की राशि से संपत्ति अर्जित करने के तथ्य सामने आए।
ठगी की रकम से खरीदी कार जब्त
विवेचना में पाया गया कि आरोपी ने ठगी की राशि से एक कार (क्रमांक सीजी 15 के 0226) खरीदी थी, जिसकी मासिक किस्त 24,700/- अदा की जा रही थी। पुलिस ने 27 मार्च 2026 को उक्त वाहन को आरोपी के कब्जे से जब्त कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद न्यायिक अभिरक्षा
पुलिस ने आरोपी को 27 मार्च 2026 को शाम 4:30 बजे गिरफ्तार किया और नियमानुसार उसकी पत्नी बसंती को सूचना दी, आरोपी को न्यायालय बंकेटपुर में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश पर उसे जिला जेल बंकेटपुर भेज दिया गया।
वर्षि अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सुरेशा चौबे तथा एसडीओपी राजेश साहू के निर्देशन में की गई, थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रमोद पांडे एवं प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस की अपील
थाना पटना पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी अज्ञात व्यक्ति को धनराशि न दें, किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

रायपुर निगम में 2130 करोड़ का बजट पेश

पंडरी-नरैया में वुमन हॉस्टल, शंकर-नगर-डूमरतराई में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक-मार्केट

रायपुर, 30 मार्च 2026। रायपुर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मेयर मीनल चौबे ने 2130 करोड़ 35 लाख 13 हजार रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि, पंडरी और नरैया तालाब में विक्रम वुमन हॉस्टल बनाया जाएगा।



महापौर ने जनता को ठगने का काम किया- नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि, महापौर ने जनता को ठगने का काम किया है। टैक्स में छूट के वादे का कोई जिक्र नहीं है। पिछले बजट की घोषणाओं को अब तक पूरा नहीं किया गया।

तभी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वहीं, विपक्ष ने कहा कि पहले अधूरी वादों पर चर्चा हो, तभी तख्ता वापस रखी जाएगी। इसके अलावा विपक्षी पार्षदों पर कारवाही को लेकर सभापति और एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा के बीच तीखी बहस भी हुई।

निगम की बड़ी घोषणाएं

- पंडरी और नरैया तालाब में बनाया जाएगा।
- विक्रम वुमन हॉस्टल बंदे अपराधों को रोकने के लिए 140 लाख की लागत से 268 कैमरे लगाए गए।
- नारैया परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी और युथ हॉस्टल बनाया जाएगा।
- शंकर नगर और डूमरतराई में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट।
- इसके निर्माण के लिए 100 करोड़ का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा।
- नगर निगम मुख्यालय और पंडरी में ऑटोमैटिक पार्किंग बनेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बड़ते अपराधों को रोकने के लिए 140 लाख की लागत से 268 कैमरे लगाए गए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर घोषणा

- सड़क चौड़ाकरण और नगर विकास योजनाओं के लिए 120 करोड़ रुपए।
- आवास योजना के लिए 45 करोड़ रुपए
- नवीन और जल शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के लिए बजट प्रावधान।
- शहर में नए सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे।

पुलिस विभाग में 16 अधिकारियों का डीएसपी पद पर प्रमोशन

रायपुर, 30 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने पुलिस विभाग में कार्यरत 16 निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को डीएसपी (उप पुलिस अधीक्षक) पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 24 मार्च 2026 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया। अधिकारियों को पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (56,100 - 1,77,500 रुपए) में की गई है। पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। पदोन्नति में शामिल अधिकारी निरीक्षक संवर्ग, कंपनी कमांडर और विशेष शाखा के हैं। इनके पदोन्नत होने के बाद ये डीएसपी संवर्ग विशेष शाखा में शामिल होंगे। कंपनी कमांडर पद पर प्रमोटे होने वाले प्रमुख अधिकारियों में बृजेश कुमार भदौरिया, अविनाश कुमार अग्निहोत्री, हरीश कुमार तिवारी, अमित शर्मा, मनोप कुमार साहू, शैलेन्द्र कुमार सेन, देव नाथय सिंह, इन्द्रसेन बंजारे, मिलमल मिश्र, ओमप्रकाश सेन, राकेश कुमार सलाम, राम बहादुर शर्मा और शब्बीर अली शामिल हैं। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों का पदस्थापना आदेश अलग से जारी किया जाएगा। अधिकारियों को इस पदोन्नति से विभाग में नयापन आया और पुलिस विभाग के प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था कार्यों में मजबूती



बढ़ेगी। पिछले वर्षों में पुलिस विभाग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों और कंपनी कमांडरों को पदोन्नति देने का क्रम जारी रखा है। इस बार भी यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत पूरी की गई है। अधिकारियों की लंबी सेवाओं, अनुशासन और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें डीएसपी पद पर पदोन्नति दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने बताया कि डीएसपी पद पर पदोन्नति प्राप्त अधिकारी अब अपने-अपने क्षेत्र और जिम्मेदारियों में और अधिक प्रभावी तरीके से काम करेंगे। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी अधिकारियों की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस पदोन्नति से पुलिस विभाग की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों की भूमिका और मजबूत होगी।

छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा रेट में 5 की बढ़ोतरी

1 अप्रैल से लागू होगी नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की नई दरें

बिलासपुर, 30 मार्च 2026। नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ से अलग-अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाइवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अम्बिकापुर, रायगढ़ समेत सभी टोल प्लाजा में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 अप्रैल से हर टोल प्लाजा से गुजरने पर 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। इसी तरह अनुअल (वार्षिक) पासधारकों को 75 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। राहत की बात है कि, स्थानीय पासधारकों को पुराने दर पर ही सफर करने की छूट है। नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनल शिफ्ट इयर 2026-27 के लिए टोल की नई दरें जारी कर दी हैं। बिलासपुर जिले के 4 प्रमुख टोल प्लाजा भाजपुरी,

मुताबिक, ये बढ़ोतरी 5 से लेकर 20 रुपए तक की है। रिंग रोड पर प्राइवेट के अलावा हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहां केवल भारी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल रेटों में 5 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है।

सालाना पास के लिए 3075 रुपए देने होंगे : नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने कार के लिए बनाए जाने वाले सालाना पास की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की। ये बढ़ोतरी भी 1 अप्रैल से लागू होगी। अभी सालाना पास 3 हजार रुपए में बनता है, जिसमें 200 टोल बूथ क्रॉस करने की लिमिट होती है। 1 अप्रैल से बनने वाले सालाना पास के लिए अब 3075 रुपए देने पड़ेंगे।

आधुनिक तकनीक के साथ संवेदनशीलता ही नई पुलिसिंग की पहचान है : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 30 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय चंद्रकुंभर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित उप निरीक्षक संवर्ग के दीक्षांत (पासिंग आउट परेड) समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर सुबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर संवर्ग के अधिकारियों को सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस सत्र में कुल 859 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिनमें 54 सुबेदार, 528 उप निरीक्षक (जीडी), 02 उप निरीक्षक (कंयूटर), 01 उप निरीक्षक (रेडियो), 01 उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह), 68 उप निरीक्षक (एसबी) तथा 205 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह दिन सभी प्रशिक्षुओं के जीवन का एक यादगार पड़ाव है, जहाँ से वे राष्ट्र और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कठोर प्रशिक्षण के बाद प्राप्त यह उपलब्धि न केवल प्रशिक्षुओं के लिए, बल्कि उनके परिवारों और पूरे प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले वर्ष जब उन्होंने इन्हीं युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, तब उनके पास प्रतिभा थी, और आज प्रशिक्षण के बाद उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का समावेश हो चुका है, जो उन्हें एक सफल अधिकारी बनाएगा। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस सेवा को अत्यंत प्रतिष्ठित एवं जिम्मेदारीपूर्ण बताया है, बल्कि किसी भी प्रतिष्ठित सेवा



का आधार सत्यनिष्ठा होती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिस का मूल दायित्व नागरिकों की रक्षा करना है। जब भी कोई नागरिक असुरक्षित महसूस करता है, तो सबसे पहले पुलिस के पास ही जाता है। इसलिए जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्दी केवल अधिकार नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा का संकल्प और उससे जुड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जिसे हर परिस्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी कभी आसान नहीं होती, लेकिन क्षमता और समर्पण के साथ इसे सफलतापूर्वक निभाया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान किए गए कठिन परिश्रम की तरह ही सेवा में भी निरंतर प्रयास और समर्पण से सतों और सफलता प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज का यह निष्क्रमण केवल अकादमी से बाहर निकलना नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यक्षेत्र में प्रवेश का संकेत है। उन्होंने इसे सनातन परंपरा के 'निष्क्रमण संस्कार' से जोड़ते हुए बताया कि जैसे शिशु पहली बार घर से बाहर निकलता है, उसी प्रकार आज ये प्रशिक्षु सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण से निकलकर व्यापक जिम्मेदारियों वाले सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी एवं त्वरित बनाया गया है, आधुनिक तकनीक और उपकरणों को पुलिस बल में शामिल किया गया है तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों स्थापित की गई हैं। साथ ही प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और आधुनिक स्वरूप दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य की पुलिस केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं होगी, बल्कि एक सक्रिय सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी, जिसके लिए उसे प्रतिक्रियात्मक से सक्रियात्मक एंजेंसी में

रूपांतरित होना होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश वर्तमान में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें अतिनिवेशिक कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सशस्त्र अधिनियम जैसे नए कानून लागू किए गए हैं। यह दीक्षांत समारोह इस दृष्टि से विशेष महत्व रखता है कि यह उप निरीक्षकों का पहला बैच है, जिसने इन नवीन संहिताओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये अधिकारी इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा, विकास और विश्वास इन तीन स्तंभों पर कार्य कर रही है और पुलिस की भूमिका इन तीनों को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज से जुड़कर लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र डर से जीता जा सकता है, लेकिन दिल केवल विश्वास से ही जीता जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में स्पर्ट, तकनीक-संचालित और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पुलिस डिजिटल, तकनीकी और उन्नत साधनों से लैस होगी, लेकिन जनता का विश्वास केवल व्यवहार, आचरण और निष्ठा से ही अर्जित किया जा सकता है।

मीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज

रायपुर, 30 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में झुलसाती गर्मी के बीच अब मौसम कर्वट लेने वाला है। फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

रायपुर, 30 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में झुलसाती गर्मी के बीच अब मौसम कर्वट लेने वाला है। फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

जंगल में मिला हथियारों का जखीरा... एके-47, इंसोस रायफल समेत अन्य सामान बरामद

मोहला-मानपुर, 30 मार्च 2026। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। घने जंगलों में छिपाकर रखा गया माओवादियों का हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, जिसमें एके-47 और इंसोस रायफल जैसे घातक हथियार शामिल हैं। यह ऑपरेशन मोहला-मानपुर के बस्तर सीमावर्ती इलाके में चलाया गया, जहां डीआरजी और Indo-Tibetan Border Police के जवानों ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में दखिशा दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान कांकर जिले के उयकाटोला, कोवाचोटीला और मानपुर ब्लॉक के कलवर गांव के बीच जंगल में एक गुड्डे में छिपाया गया नक्सल डंप मिला। इस डंप से एक एके-47, एक इंसोस रायफल, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य हथियार संबंधी सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने सभी हथियारों को जप्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि ये जखीरा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपाया गया था, जिसे समय रहते बरामद कर लिया गया। गौरतलब है कि इसी इलाके में पहले भी माओवादियों की गतिविधियां सामने आती रही हैं, और हाल ही में आरकेबी डिवीज के पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था।

मोहला-मानपुर, 30 मार्च 2026। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। घने जंगलों में छिपाकर रखा गया माओवादियों का हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, जिसमें एके-47 और इंसोस रायफल जैसे घातक हथियार शामिल हैं। यह ऑपरेशन मोहला-मानपुर के बस्तर सीमावर्ती इलाके में चलाया गया, जहां डीआरजी और Indo-Tibetan Border Police के जवानों ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में दखिशा दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान कांकर जिले के उयकाटोला, कोवाचोटीला और मानपुर ब्लॉक के कलवर गांव के बीच जंगल में एक गुड्डे में छिपाया गया नक्सल डंप मिला। इस डंप से एक एके-47, एक इंसोस रायफल, भारी मात्रा में कारतूस और अन्य हथियार संबंधी सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने सभी हथियारों को जप्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि ये जखीरा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपाया गया था, जिसे समय रहते बरामद कर लिया गया। गौरतलब है कि इसी इलाके में पहले भी माओवादियों की गतिविधियां सामने आती रही हैं, और हाल ही में आरकेबी डिवीज के पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था।

प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी, दो दिन में दूसरी बड़ी घटना से इलाके में फैली सनसनी

महासमुंद, 30 मार्च 2026। जिले से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पिथौरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि दो दिनों के भीतर इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिससे पूरे इलाके में भय और चर्चा का माहौल बन गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृत युवती खल्लारी थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि युवक पटेवा क्षेत्र का निवासी है। दोनों के शव एक ही स्थान पर फांसी के फंदे से लटकते मिले, जिससे यह मामला प्रेम संबंध से जुड़ा माना जा रहा है। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक, युवती के हाथ पर गोदने से 'अकिता' नाम लिखा हुआ है। वहीं पास में मिले आधार कार्ड के आधार पर उसे नाबालिग बताया जा रहा है, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

महासमुंद, 30 मार्च 2026। जिले से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पिथौरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि दो दिनों के भीतर इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिससे पूरे इलाके में भय और चर्चा का माहौल बन गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृत युवती खल्लारी थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि युवक पटेवा क्षेत्र का निवासी है। दोनों के शव एक ही स्थान पर फांसी के फंदे से लटकते मिले, जिससे यह मामला प्रेम संबंध से जुड़ा माना जा रहा है। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक, युवती के हाथ पर गोदने से 'अकिता' नाम लिखा हुआ है। वहीं पास में मिले आधार कार्ड के आधार पर उसे नाबालिग बताया जा रहा है, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

पढ़ाई सीबीएसई की, एग्जाम छत्तीसगढ़ बोर्ड का! बिलासपुर के स्कूलों की मनमानी पर हाईकोर्ट का शिकंजा

बिलासपुर, 30 मार्च 2026। शहर के दो नामी निजी स्कूलों- ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और नारायणा टेक्नो स्कूल-की बड़ी लापरवाही और मनमानी उजागर हुई है। आरोप है कि पूरे साल छात्रों को सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई कराई गई, लेकिन परीक्षा के समय उन्हें छत्तीसगढ़ बोर्ड का पेपर देने के लिए मजबूर कर दिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार, इन स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8 वीं के छात्रों को पूरे साल सीबीएसई सिलेबस के तहत पढ़ाया गया। अभिभावकों का आरोप है कि सीबीएसई के नाम पर उनसे भारी फीस भी वसूली गई।



स्कूल प्रबंधन ने फरवरी में आंतरिक परीक्षा भी ले ली थी। विवाद तब खड़ा हुआ जब राज्य सरकार ने इस वर्ष 5 वीं और 8 वीं की परीक्षाएं बोर्ड स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। चूंकि संबंधित स्कूलों के पास सीबीएसई की मान्यता नहीं थी, इसलिए प्रबंधन ने छात्रों पर छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि जब अंत में छत्तीसगढ़ बोर्ड का ही एग्जाम दिलाया था, तो सीबीएसई के नाम पर फीस क्यों ली गई।

हाईकोर्ट में मामला, सरकार से जवाब तलब : यह मुद्दा शिक्षा के अधिकार से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा सचिव को विस्तृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से दलील दी गई कि सीबीएसई ने मान्यता के नियम कड़े कर दिए हैं, जिसके तहत अब केवल 12 वीं तक संचालित स्कूलों को ही मान्यता मिल रही है। कोर्ट ने इस पर विस्तृत जांचकी मांगी है।

रायपुर निगम ने 2 होली-क्रॉस स्कूलों को किया सील, 58 लाख प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

रायपुर, 30 मार्च 2026। रायपुर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने दो बड़े स्कूलों पर कार्रवाई की है। प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने पर बैनबाजार और शैलेन्द्र नगर के होली क्रॉस स्कूलों को सील कर दिया। बैनबाजार के स्कूल पर करीब 34 लाख रुपए और शैलेन्द्र नगर स्थित स्कूल पर करीब 24 लाख रुपए का बकाया था। निगम ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और दोनों परिसरों के मुख्य गेट पर ताला



लगाकर सीलबंदी की कार्रवाई की। यह कार्रवाई नगर निगम जेन-4 के तहत की गई, जहां जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने अभियान चलाया।

महतारी वंदन योजना : अब थंब इंप्रेशन से साबित करनी होगी पहचान, 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य

रायपुर, 30 मार्च 2026। महतारी वंदन योजना लागू होने के बाद से सरकार ने पहली बार ऐसा आदेश दिया है। जिसके तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को सीएससी सेंटरों में जाकर बायोमेट्रिक पहचान साबित करनी होगी। इससे यह पता चलेगा कि लाभार्थियों में कितने जीवित और पात्र हैं। भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित हुई इस योजना में कड़वाई नहीं की गई थी। जो भी पात्रता के मापदंड थे, उसके हिसाब से महिलाओं का सत्यापन नहीं हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग ने फिल्टर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया।

अपात्रों की छंट्टाई के लिए बनाया गया सख्त मैकेनिज्म : गौरतलब है कि मात्रा वंदन



योजना में अपात्रों की छंट्टाई की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। मार्च 2024 से लागू योजना में केवल आधार कार्ड और उससे लिंकड एकाउंट देने पर ही पंजीयन हो गया। कई महिलाओं ने तो जाकर लिंक भी नहीं कराया। एकाउंट नंबर भी

गलत दिए गए। वैवाहिक स्थिति की जानकारी भी गलत दी गई। धीरे-धीरे ऐसे हितग्राहियों को डाटाबेस से फिल्टर किया जा रहा है।

30 जून तक बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य : इस तरह एक अप्रैल से 30 जून के बीच सभी महिलाओं को सीएससी सेंटर में पहुंचकर बायोमेट्रिक पहचान दर्ज करानी होगी। सरकार देखना चाहती है कि जिस महिला को जिस जगह पर लाभ दिया जा रहा है, वह उस स्थान पर मौजूद है या नहीं। इसके पहले मोबाइल नंबर, नाम और आधार कार्ड में अंतर मिलने पर पेमेंट श्लैट किया जा रहा है। सरकार ने आदेश दिया है कि हर महिला को सीएससी सेंटर में जाकर उपस्थिति देनी होगी।